North Asian International Research Journal of Multidisciplinary

ISSN: 2454-2326 Vol.12, Issue, 1 January-2026

UGC-Aligned | HEI-Recognized PR Journal (Under New UGC Guidelines)

Page.No. 1-27

अस् थरि बाां ग् लादेश : भारत की राष् ट् रीय सुरक् ष ा पर सामररक प् रभाव ”

(“Bangladesh in Turmoil: Strategic Implications for India’s National Security “)

Dr.Arvind Kumar

Assistant professor Department of Defence and strategic studies. ANDKPG College Gonda.

Affiliated to Maa Pateswari University .

Article History
Received: 01 Dec. 2025
Revised: 16 Dec. 2025
Accepted: 01 Jan.2026
Published Online: 01 Jan. 2026

सारांश (Abstract) :

दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य में बांग्लादेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है, जिसकी आंतरिक स्थिरता न केवल उसकी घरेलू राजनीति और समाज को प्रभावित करती है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से भी गहराई से जुड़ी हुई है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत तनाव, लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण, सामाजिक ध्रुवीकरण तथा आर्थिक दबावों जैसी बहुआयामी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव, नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रश्न, युवाओं और श्रमिक वर्ग में असंतोष तथा कट्टरपंथी तत्वों की संभावित पुनर्सक्रियता ने देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति को जटिल बना दिया है। यह उथल-पुथल केवल एक आंतरिक मामला नहीं रह जाती, बल्कि इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत-बांग्लादेश सीमा, उत्तर-पूर्वी भारत की सुरक्षा, अवैध प्रवासन, सीमा-पार अपराध, उग्रवाद और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर पड़ता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध अत्यंत गहरे रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की अस्थिरता भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश की समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती के रूप में उभरती है। विशेष रूप से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की संवेदनशीलता, बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा, चीन और अन्य बाहरी शक्तियों की बढ़ती सक्रियता तथा क्षेत्रीय प्रभाव-क्षरण की आशंका भारत की रणनीतिक चिंताओं को और बढ़ाती है।

इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य बांग्लादेश में जारी राजनीतिक-सामाजिक अस्थिरता का विश्लेषण करना और यह स्पष्ट करना है कि यह स्थिति भारत की आंतरिक, सीमा और भू-राजनीतिक सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है। साथ ही, अध्ययन का लक्ष्य यह भी है कि भारत के लिए उभरती सुरक्षा चुनौतियों, संभावित जोखिमों और रणनीतिक दुविधाओं की पहचान की जाए, ताकि भविष्य के लिए एक संतुलित और यथार्थवादी नीति-दृष्टि विकसित की जा सके।

कार्यप्रणाली की दृष्टि से यह अध्ययन गुणात्मक (Qualitative) पद्धति पर आधारित है। इसमें द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का व्यापक उपयोग किया गया है, जिनमें शैक्षणिक पुस्तकों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं, नीति-पत्रों, थिंक-टैंक रिपोर्ट्स, समाचार-पत्रों तथा विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का विश्लेषण शामिल है। समग्र रूप से यह शोध बांग्लादेश की अस्थिरता और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अंतर्संबंधों को एक समग्र, विश्लेषणात्मक और रणनीतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

शोध अंतर (Research Gap):

(1) *सीमित समग्र विश्लेषण:* वर्तमान अध्ययन में बांग्लादेश की राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता के कारणों पर अधिकांश शोध केवल आंतरिक दृष्टिकोण से केंद्रित हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विस्तृत और समग्र विश्लेषण अभी तक पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है।

(2). *बहुपक्षीय रणनीतिक दृष्टिकोण की कमी:* कई शोध बांग्लादेश में बाहरी शक्तियों (जैसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका) की भूमिका को केवल आंशिक रूप से देखते हैं। भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके व्यापक प्रभावों का व्यवस्थित अध्ययन अब तक अपर्याप्त है।

(2) *भविष्य जोखिम और नीति सुझावों का अभाव.:* मौजूदा साहित्य में बांग्लादेश अस्थिरता से उत्पन्न दीर्घकालीन सुरक्षा चुनौतियों और नीति निर्धारण के व्यावहारिक विकल्पों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। विशेष रूप से भारत के लिए संभावित रणनीतिक उपायों और क्षेत्रीय सहयोग पर विश्लेषण सीमित है

भूमिका (Introduction):

दक्षिण एशिया की सामरिक भू-राजनीति में बांग्लादेश का स्थान केवल एक पड़ोसी राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री रणनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश के निर्माण से लेकर आज तक, भारत–बांग्लादेश संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामरिक स्तरों पर एक विशिष्ट निकटता का उदाहरण रहे हैं। भारत ने न केवल बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि उसके बाद भी आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, जल-साझेदारी और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया है। तथापि, हाल के वर्षों में बांग्लादेश की आंतरिक परिस्थितियों में उत्पन्न अस्थिरता ने इन संबंधों के भविष्य तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

वर्तमान परिदृश्य में बांग्लादेश राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते दबाव और गहरे होते आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्न, विपक्ष की सीमित राजनीतिक भागीदारी, तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश—इन सभी कारकों ने बांग्लादेश को एक “fragile democracy” की श्रेणी के निकट ला खड़ा किया है। इसके समानांतर, आर्थिक मोर्चे पर विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, बढ़ती महँगाई, ऊर्जा संकट और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) पर बढ़ती निर्भरता ने

सामाजिक असंतोष को और तीव्र किया है। इतिहास गवाह है कि जब किसी राज्य में राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरता गहराती है, तो उसके प्रभाव सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पड़ोसी देशों की सुरक्षा संरचना को भी प्रभावित करते हैं।

भारत के संदर्भ में बांग्लादेश का महत्व और भी अधिक संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा है, जो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। यह सीमा भारत के संवेदनशील उत्तर-पूर्वी राज्यों—असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल—से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिरता का सीधा प्रभाव अवैध प्रवासन, सीमा-पार तस्करी, उग्रवादी नेटवर्कों की पुनः सक्रियता तथा कट्टरपंथी तत्वों की घुसपैठ के रूप में भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ सकता है। अतीत में ULFA, NDFB जैसे उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेशी भू-भाग के दुरुपयोग के उदाहरण इस आशंका को और प्रासंगिक बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश भारत की North-East Connectivity की रणनीति का केन्द्रीय स्तंभ है। 'एक्ट ईस्ट नीति' के अंतर्गत भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, मल्टी-मॉडल ट्रांजिट, तथा दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ाव बांग्लादेश की स्थिरता पर निर्भर करता है। किसी भी प्रकार की आंतरिक अव्यवस्था इन परियोजनाओं को न केवल बाधित कर सकती है, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक-रणनीतिक योजनाओं को भी कमजोर कर सकती है।

सामरिक दृष्टि से, बांग्लादेश की भूमिका बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में और भी निर्णायक हो जाती है। यह क्षेत्र भारत की समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति मार्गों और Indo-Pacific रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। बांग्लादेश में बढ़ती अस्थिरता अथवा बाहरी शक्तियों—विशेषकर चीन—का बढ़ता प्रभाव, भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है।

इसी पृष्ठभूमि में यह शोध-पत्र यह केंद्रीय तर्क प्रस्तुत करता है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरता का भारत की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा पर प्रत्यक्ष "spillover effect" पड़ता है। यह अध्ययन यह विश्लेषण करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार राज्य-अस्थिरता, सीमा-पार सुरक्षा

चुनौतियों, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समुद्री रणनीति के माध्यम से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। समकालीन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, यह शोध भारत के लिए बांग्लादेश संकट के रणनीतिक निहितार्थों को समझने और नीति-निर्माण के लिए एक सुदृढ़ विश्लेषणात्मक आधार प्रदान करता है।

भारत – बांग्लादेश सम्बन्धों का ऐतिहासिक संदर्भ :

(Historical Context: India–Bangladesh Relations:)

भारत–बांग्लादेश संबंध दक्षिण एशिया के सबसे गहरे, जटिल और रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों में से एक रहे हैं। इन संबंधों की ऐतिहासिक जड़ें केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक और संघर्षजन्य अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक, बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता और राजनीतिक दिशा ने भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पूर्वी पड़ोस नीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि एक स्थिर और सहयोगी बांग्लादेश भारत के लिए क्यों लाभकारी रहा है और अस्थिरता क्यों रणनीतिक चिंता का विषय बन जाती है।

1971 का मुक्ति संग्राम और भारत की भूमिका :

1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भारत–बांग्लादेश संबंधों की आधारशिला है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक दमन, भाषाई असमानता और सैन्य अत्याचारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न मानवीय संकट ने भारत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। लगभग एक करोड़ शरणार्थियों का भारत में प्रवेश केवल मानवीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा चुनौती भी था। भारत ने न केवल शरणार्थियों को आश्रय दिया, बल्कि मुक्ति वाहिनी को राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य समर्थन प्रदान किया।

दिसंबर 1971 में भारत–पाक युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय भारत की विदेश नीति की एक ऐतिहासिक सफलता के रूप में देखा गया। इस संघर्ष ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास (strategic trust) की नींव रखी, जिसने प्रारंभिक वर्षों में घनिष्ठ सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया।

शेख मुजीबुर रहमान से शेख हसीना युग तक :

स्वतंत्रता के बाद शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में भारत–बांग्लादेश संबंध स्वाभाविक रूप से मैत्रीपूर्ण रहे। 1972 की भारत–बांग्लादेश मैत्री संधि ने सहयोग, संप्रभुता के सम्मान और क्षेत्रीय शांति के सिद्धांतों को संस्थागत रूप दिया। हालांकि, 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद बांग्लादेश की राजनीति में अस्थिरता आई और सैन्य शासन के दौर में संबंधों में दूरी बढ़ी।

1990 के दशक के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली और विशेष रूप से शेख हसीना के नेतृत्व में भारत–बांग्लादेश संबंधों को नई दिशा मिली। हसीना सरकार ने भारत के साथ सुरक्षा सहयोग, उग्रवाद विरोधी कार्रवाई और कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी। इस कालखंड में संबंध केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि हित-आधारित रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुए।

भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement), 2015

भारत–बांग्लादेश संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ 2015 का भूमि सीमा समझौता (LBA) रहा। दशकों से लंबित एन्क्लेव समस्या का शांतिपूर्ण समाधान दोनों देशों की राजनीतिक परिपक्वता और आपसी विश्वास का प्रतीक था।

इस समझौते ने न केवल सीमावर्ती आबादी को नागरिक अधिकार और स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि सीमा प्रबंधन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और द्विपक्षीय विश्वास को भी सुदृढ़ किया। LBA को दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण सीमा समाधान के एक मॉडल केस के रूप में देखा जाता है।

सुरक्षा सहयोग और पूर्वोत्तर भारत

भारत के लिए बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उसकी सुरक्षा सहयोग नीति रही है, विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में। शेख हसीना सरकार के दौरान बांग्लादेश ने ULFA, NDFB जैसे उग्रवादी संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई की और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया सहयोग को गहरा किया।

इस सहयोग का प्रत्यक्ष परिणाम पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद की तीव्रता में कमी, विकास परियोजनाओं को गति और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार के रूप में सामने आया। यह स्पष्ट करता है कि बांग्लादेश की स्थिरता भारत की आंतरिक सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है।

व्यापार, ट्रांजिट और कनेक्टिविटी

आर्थिक और कनेक्टिविटी सहयोग भारत–बांग्लादेश संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है। द्विपक्षीय व्यापार निरंतर बढ़ा है और बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है।

ट्रांजिट और कनेक्टिविटी परियोजनाएँ—जैसे रेल, सड़क और अंतर्देशीय जलमार्ग—भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। साथ ही, बंगाल की खाड़ी तक सुगम पहुँच भारत की समुद्री रणनीति और इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण को भी मजबूती प्रदान करती है।

समकालीन बांग्लादेश में उथल-पुथल: प्रकृति एवं प्रेरक तत्व:

(Contemporary Turmoil in Bangladesh: Nature & Drivers)

समकालीन बांग्लादेश आज एक ऐसे बहुस्तरीय संकट के दौर से गुजर रहा है, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और सामाजिक-सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ एक-दूसरे को पोषित कर रही हैं। यह उथल-पुथल केवल आंतरिक शासन की समस्या नहीं है, बल्कि इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत की सुरक्षा एवं रणनीतिक हितों पर पड़ रहा है। वर्तमान संकट की प्रकृति को समझने के लिए इसके प्रमुख प्रेरक तत्वों—राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सुरक्षा आयामों—का समग्र विश्लेषण आवश्यक है।

(a) राजनीतिक अस्थिरता

बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का केंद्रबिंदु हालिया वर्षों में लगातार विवादित होते चुनाव रहे हैं। विपक्षी दलों द्वारा चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्नचिहन लगाए गए हैं और आरोप लगाया गया है कि सत्ता पक्ष ने प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा संस्थाओं का राजनीतिक उपयोग किया। चुनावों में विपक्ष की

सीमित भागीदारी और बहिष्कार ने लोकतांत्रिक वैधता को कमजोर किया है, जिससे शासन और जनता के बीच विश्वास का संकट गहराया है।

इसके साथ-साथ विपक्षी दलों और असहमति की आवाज़ों के दमन के आरोप भी लगातार सामने आए हैं। राजनीतिक गिरफ्तारियाँ, मीडिया पर दबाव और नागरिक समाज की सीमित भूमिका ने एक संकुचित राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया है। यह स्थिति केवल घरेलू असंतोष तक सीमित नहीं रही, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की लोकतांत्रिक साख को प्रभावित कर रही है।

लोकतांत्रिक पतन (Democratic Backsliding) को लेकर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं ने बांग्लादेश को कूटनीतिक दबाव की स्थिति में ला खड़ा किया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर पड़ती भूमिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष मीडिया पर प्रश्न, शासन की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं।

(b) आर्थिक दबाव

राजनीतिक अस्थिरता के समानांतर बांग्लादेश गंभीर आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट ने आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था को असुरक्षित बना दिया है। ऊर्जा, खाद्यान्न और औद्योगिक कच्चे माल के आयात में कठिनाइयों ने उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है।

महँगाई और बेरोजगारी में वृद्धि ने आम नागरिक के जीवन स्तर को प्रभावित किया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और रोजगार के अवसरों में कमी ने सामाजिक असंतोष को जन्म दिया है, जो राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा करता है। विशेषकर शहरी मध्यम वर्ग और निम्न-आय वर्ग में बढ़ता आर्थिक तनाव शासन के प्रति असंतोष का प्रमुख कारण बन रहा है।

IMF द्वारा दिया गया बेलआउट पैकेज तात्कालिक राहत तो प्रदान करता है, किंतु इसके साथ जुड़ी कठोर शर्तें—जैसे सब्सिडी में कटौती, कर सुधार और संरचनात्मक परिवर्तन—लघु अवधि में सामाजिक असंतोष

को और बढ़ा सकती हैं। आर्थिक संप्रभुता पर बाहरी निर्भरता की यह स्थिति सरकार की नीति-स्वतंत्रता को सीमित करती है और राजनीतिक विरोध को तीव्र करती है।

(c) सामाजिक एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ

आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बीच सामाजिक ताना-बाना भी तनावग्रस्त हुआ है। युवाओं में बेरोजगारी, असमानता और राजनीतिक हताशा ने कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। यद्यपि बांग्लादेश ने अतीत में आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है, फिर भी उग्रवादी संगठनों की वैचारिक पुनर्सक्रियता की आशंका बनी हुई है।

अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती रोहिंग्या शरणार्थी संकट से जुड़ी है। म्यांमार से आए लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों की दीर्घकालिक उपस्थिति ने संसाधनों पर दबाव बढ़ाया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक-सुरक्षा जोखिम उत्पन्न किए हैं। कट्टरपंथी समूहों द्वारा इस मानवीय संकट के राजनीतिक और वैचारिक दोहन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

समग्र रूप से, बांग्लादेश की समकालीन उथल-पुथल बहुआयामी है—राजनीतिक वैधता का संकट, आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक-सुरक्षा चुनौतियाँ परस्पर गुँथी हुई हैं। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश की आंतरिक स्थिरता के लिए चुनौती है, बल्कि भारत और पूरे क्षेत्र के लिए भी रणनीतिक चिंता का विषय है। एक स्थिर, लोकतांत्रिक और आर्थिक रूप से सशक्त बांग्लादेश ही क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग की आधारशिला बन सकता है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीतिक प्रभाव :

(Strategic Implications for India’s National Security):

(a) आंतरिक सुरक्षा खतरे (Internal Security Threats)

भारत की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ा खतरा दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही संगठनों का पुनरुद्धार और चरमपंथी नेटवर्क का प्रभाव है। नक्सल-माओवादी आंदोलन, जो 2000 के दशक के मध्य में लगभग 180 जिलों तक फैल चुका था, 2025 तक अपने चरम पर नहीं है लेकिन अभी भी संवेदनशील “रेड कॉरिडोर” में सक्रिय रूप से उभरता रहता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों में नक्सल प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ चुका है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए सतत चुनौती बना हुआ है।

पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न संगठनों की उपस्थिति, जैसे हाइन्येवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) और अन्य स्थानीय विद्रोही समूह, सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए जोखिम बनते हैं। इन समूहों का कुछ हिस्सा सीमापार बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य पड़ोसी देशों के जंगलों और शरण स्थलों से संचालित होता है, जिससे खुफिया एवं सामरिक चुनौतियाँ बढ़ती हैं।

इसके अतिरिक्त, ISI और अन्य चरमपंथी नेटवर्क भारत के आंतरिक माहौल में अस्थिरता फैलाने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। दक्षिण एशिया में इन एजेंसियों की रणनीति राजनीतिक विभाजन, आतंकी हमले और सामाजिक तनाव को भड़काना है ताकि भारत के प्रयासों को कमजोर किया जा सके। भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हालिया बयान ने भी इस दिशा में पाकिस्तान आधारित आतंकवादी खतरे की गंभीरता को रेखांकित किया है।

भारतीय सुरक्षा एजेंसियाँ नक़दी और हथियारों की तस्करी, अवैध भू-भागीय नेटवर्क और आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। विशेष रूप से नकली मुद्रा और हथियारों की अवैध आवाजाही, स्थानीय अतिवाद और अपराध को बढ़ावा देती है, जिससे पुलिस और खुफिया नेटवर्क पर दबाव बढ़ता है।

(b) सीमा प्रबंधन और आप्रवासन (Border Management & Migration)

भारत की सीमाओं की लंबाई लगभग 15,000 किमी है और इन्हें प्रबंधित करना एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य है। विशेष रूप से भारत-बांग्लादेश सीमा (लगभग 4,096 किमी) सुरक्षा चुनौतियों का प्रमुख केंद्र बनी हुई है जिसमें घुसपैठ, तस्करी और अवैध आव्रजन शामिल हैं। भारत-बांग्लादेश सीमा की भौगोलिक जटिलता और खुलापन, तस्करों, अवैध प्रवासियों और अपराधियों को आसान मार्ग प्रदान करता है। हाल के वर्षों में बीएसएफ की रिपोर्ट के अनुसार घुसपैठ और अपराध में कमी आई है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं और सिंगल रॉ फ़ेंस जैसी पहलों पर भी जोर दिया जा रहा है।

घुसपैठ के अलावा मानव तस्करी और मादक पदार्थों का सागर मार्ग से अवैध परिवहन भी सीमा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीएसएफ ने करोड़ों रुपये की ड्रग तस्करी को नाकाम किया है, जो यह दिखाता है कि सीमा पार अपराध नेटवर्क किस तेजी से कार्य कर सकते हैं।

सरकार ने सीमा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) लॉन्च की है, जिसमें बुनियादी ढांचे, तकनीकी समाधान और कमांड कॉन्ट्रोल नेटवर्क का समन्वय शामिल है। यह कदम भारतीय सीमाओं पर सुरक्षा, गति और निगरानी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

इन चुनौतियों के अलावा अवैध श्रमिकों और आप्रवासियों की आवाजाही से सामाजिक और आर्थिक दबाव भी उत्पन्न होता है, जो स्थानीय रोजगार, नागरिक सेवाओं और सुरक्षा ढांचे पर असर डालता है।

(c) समुद्री और बंगाल की खाड़ी सुरक्षा (Maritime & Bay of Bengal Security)

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी रणनीतिक हितों का विस्तृत दायरा शामिल है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के

लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग, तेल व गैस पाइपलाइनों का मार्ग और समुद्री संसाधनों का संरक्षण शामिल है।

चीन की समुद्री उपस्थिति इन जलमार्गों पर लगातार बढ़ रही है। चीनी नौसेना और समुद्री व्यापार नेटवर्क की गतिविधियाँ भारत सहित अन्य देशों के समुद्री हितों पर प्रभाव डाल रही हैं। भारत ने इस चुनौती का सामना करने के लिए समुद्री डोमेन अवेयरनेस बढ़ाई है, स्थानीय नौसेना और तटरक्षक बल की क्षमता मजबूत की है, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर काम किया है।

भारत सरकार ने यह भी घोषणा की है कि लगभग 250 से अधिक बंदरगाहों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) तटीय सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे, जिससे परिचालन सुरक्षा मानकों में एकरूपता आएगी।

बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत के बीच समुद्री तनाव भी देखा गया है, जहाँ बांग्लादेशी नौसेना ने मिसाइल फायरिंग अभ्यास किया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(d) भू-राजनीतिक आयाम (Geopolitical Dimension)

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध समग्र रणनीति का आधार हैं। चीन-बांग्लादेश सम्बन्ध में वृद्धि ने भारत के लिए नए रणनीतिक तनाव उत्पन्न किए हैं क्योंकि चीन अपनी आर्थिक तथा सैन्य उपस्थिति को बांग्लादेश जैसे देशों में बढ़ा रहा है। ऐसे परिवेश में भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।

जबकि भारत अपनी “Neighbourhood First” नीति के तहत बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ भरोसेमंद सम्बन्ध स्थापित करने पर जोर दे रहा है, कुछ क्षेत्रीय अस्थिरता की स्थितियों में अन्य शक्तियाँ प्रभाव बढ़ा रही हैं जो भारत के सामरिक हितों से टकराती हैं।

दक्षिण एशिया की शक्ति प्रतिष्पर्धा, विशेषकर चीन-भारत प्रबलता संतुलन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है। इस प्रतिस्पर्धा में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे साझेदारों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी भारत की समुद्री एवं भू-राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

बाहरी शक्तियों की भूमिका :

(Role of External Powers):

बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता केवल एक आंतरिक संकट नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रतिबिंब बन चुकी है। इस संकट में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान जैसी बाहरी शक्तियाँ अपने-अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इन शक्तियों की बढ़ती संलिप्तता भारत की क्षेत्रीय स्थिति, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ उत्पन्न करती है।

(क) चीन: बीआरआई परियोजनाएँ और रणनीतिक प्रभाव

चीन ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित किया है। बुनियादी ढाँचे, ऊर्जा, बंदरगाहों और संचार परियोजनाओं में चीनी निवेश ने ढाका-बीजिंग संबंधों को अभूतपूर्व स्तर तक पहुँचा दिया है। पायरा बंदरगाह, पावर प्लांट्स, पुल निर्माण और औद्योगिक पार्क जैसी परियोजनाएँ आर्थिक विकास के नाम पर चीन को दीर्घकालिक रणनीतिक पहुँच प्रदान कर रही हैं।

चीन की रणनीति केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू-रणनीतिक है। बांग्लादेश, चीन के लिए हिंद महासागर तक पहुँच का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है, जो “मलक्का दुविधा” को कम करने की उसकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश में चीनी हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सहयोग ने बीजिंग को ढाका की सुरक्षा नीति में भी प्रभावशाली बना दिया है।

भारत के दृष्टिकोण से यह स्थिति चिंताजनक है क्योंकि इससे रणनीतिक घेरेबंदी (Strategic Encirclement) की आशंका बढ़ती है। म्यांमार, श्रीलंका और अब बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति भारत के पूर्वी समुद्री और स्थलीय सुरक्षा पर दबाव उत्पन्न करती है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में चीन का झुकाव किसी भी ऐसे शासन की ओर हो सकता है जो उसके निवेश और हितों की रक्षा करे, भले ही वह लोकतांत्रिक मानकों से समझौता करता हो।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका: लोकतंत्र, मानवाधिकार और दबाव की राजनीति

संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका अपेक्षाकृत अलग किंतु उतनी ही प्रभावशाली रही है। अमेरिका ने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, निष्पक्ष चुनाव, मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर लगातार चिंता व्यक्त की है। वीज़ा प्रतिबंध, चुनावी निगरानी और सार्वजनिक वक्तव्यों के माध्यम से वाशिंगटन ने ढाका पर दबाव बनाए रखा है।

हालाँकि, यह दबाव केवल नैतिक या लोकतांत्रिक मूल्यों तक सीमित नहीं है। अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वह नहीं चाहता कि बांग्लादेश पूरी तरह चीन के प्रभाव क्षेत्र में चला जाए। इसी कारण लोकतंत्र और मानवाधिकार का विमर्श कई बार रणनीतिक साधन (Strategic Instrument) के रूप में प्रयोग होता दिखाई देता है।

इस दोहरे दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ है कि बांग्लादेशी राजनीति में अमेरिका को लेकर ध्रुवीकरण बढ़ा है। कुछ वर्ग इसे पश्चिमी हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि कुछ इसे लोकतांत्रिक समर्थन के रूप में देखते हैं। भारत

के लिए चुनौती यह है कि वह अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा में फँसे बिना बांग्लादेश के साथ अपने पारंपरिक विश्वास और सहयोग को बनाए रखे।

(ग) पाकिस्तान: खुफिया नेटवर्क और अस्थिरता का आयाम

पाकिस्तान की भूमिका अपेक्षाकृत छिपी हुई किंतु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में भारत-विरोधी तत्वों, कट्टरपंथी समूहों और कुछ राजनीतिक नेटवर्कों के साथ संपर्क बनाए रखा है। हालिया अस्थिरता के संदर्भ में यह आशंका फिर से प्रबल हुई है कि बांग्लादेश की धरती का उपयोग भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा सकता है।

नकली मुद्रा, हथियारों की तस्करी, और चरमपंथी विचारधाराओं का प्रसार ऐसे माध्यम रहे हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान अप्रत्यक्ष रूप से भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करता रहा है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में ये नेटवर्क अधिक सक्रिय हो सकते हैं, जिससे भारत-बांग्लादेश सुरक्षा सहयोग कमजोर पड़ने का खतरा उत्पन्न होता है।

(घ) भारत की चिंता: रणनीतिक प्रभाव का क्षरण और सुरक्षा जोखिम

इन सभी बाहरी शक्तियों की सक्रियता के बीच भारत की सबसे बड़ी चिंता अपने रणनीतिक प्रभाव का क्षरण है। एक स्थिर, मित्रवत और सहयोगी बांग्लादेश भारत के लिए उत्तर-पूर्वी संपर्क, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज़ से अनिवार्य रहा है। किंतु यदि बांग्लादेश बाहरी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में अधिक गहराई से प्रवेश करता है, तो भारत की “Neighbourhood First” नीति को गंभीर झटका लग सकता है।

इसके अतिरिक्त, भारत को यह भी समझना होगा कि केवल सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। आर्थिक सहयोग, जन-संपर्क, सांस्कृतिक कूटनीति और विकास साझेदारी के माध्यम से भारत को बांग्लादेशी समाज में अपनी सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करना होगा। अन्यथा, बाहरी शक्तियाँ राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर भारत-विरोधी विमर्श को और गहरा कर सकती हैं।

इससे स्पष्ट होता है की बांग्लादेश में बाहरी शक्तियों की भूमिका बहुआयामी और प्रतिस्पर्धात्मक है। चीन आर्थिक-रणनीतिक विस्तार चाहता है, अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर रणनीतिक संतुलन साध रहा है, और पाकिस्तान अस्थिरता के अवसर तलाश रहा है। इस जटिल परिदृश्य में भारत के लिए चुनौती केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक, बहु-आयामी और संवेदनशील रणनीति अपनाने की है। बांग्लादेश की स्थिरता, संप्रभुता और विकास में सहयोग ही भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय नेतृत्व की कुंजी है।

नीति प्रतिक्रिया और रणनीतिक विकल्प :

(Policy Response & Strategic Options :)

भारत की बदलती विदेश नीति और रणनीतिक विकल्प को आज एक सुदृढ़, संतुलन-आधारित एवं क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित नीति के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले, राजनयिक सगाई बिना हस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल दिए बिना विश्वास-आधारित संबंध स्थापित करना है। यह नीति विशेष रूप से पड़ोसी पहले (Neighbourhood First) नीति के तहत प्रभावी हुई है, जहाँ भारत ने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और मानवीय सहयोग को बढ़ाया है जिससे पारस्परिक विश्वास और सहयोग का आधार मजबूत हुआ है।

इस दृष्टिकोण का लाभ यह है कि यह क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करता है और एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें सभी देश अपनी संप्रभुता बनाए रखते हुए सहयोग कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बल मिलता है।

राजनयिक संवाद के साथ-साथ सुरक्षा सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करना भी भारत की विदेश नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनज़र भारत ने खुफिया साझेदारी,

साइबर सुरक्षा सहयोग, सीमावर्ती आतंकवाद विरोधी अभियानों और समुद्री सुरक्षा में संयुक्त प्रयासों को महत्व दिया है। यह साझेदारी न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा को भी मजबूती देती है। इस तरह की साझेदारी से क्षेत्रीय देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा खुफिया नेटवर्क विकसित हुए हैं, जो आतंकवाद, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों के मार्गों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं।

भारत का आर्थिक एवं विकास कूटनीति (Economic & Development Diplomacy) दृष्टिकोण भी गतिशील और रणनीतिक है। अब यह केवल द्विपक्षीय व्यापार समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास सहायता, तकनीकी सहयोग, लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) और व्यापार-निवेश संवर्द्धन प्रयासों को भी सम्मिलित करता है। भारत ने 160 से अधिक देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग प्रदान किया है, जो उसकी विकास कूटनीति की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अलावा भारत ने मुक्त व्यापार समझौतों और वस्तु तथा सेवा व्यापार सौदों के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों में अपनी भागीदारी बढ़ाई है, जैसे ASEAN के साथ व्यापार करार को अद्यतन करने की पहल।

यह आर्थिक कूटनीति न केवल भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाती है, बल्कि रणनीतिक साझेदारियों को भी गहरा करती है।

सीमा प्रबंधन सुधार (Border Management Reforms) भी भारत की सुरक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं पर संयुक्त कार्य कर रहे हैं ताकि अवैध गतिविधियों, मानव तस्करी तथा सीमा पार अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

इसके साथ ही भारत ने सीमा सुरक्षा बलों (BSF, SSB) के बीच समन्वय, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे (जैसे सीमा सड़क परियोजनाएँ) और निगरानी प्रणालियों में सुधार पर बल दिया है, जिससे सीमा पर स्थिति का वास्तविक-समय में विश्लेषण तथा तेज़ प्रतिक्रिया संभव हो सके। ये सुधार भारत को सीमा पर बढ़ती चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं और सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को कम करते हैं।

एक अन्य केंद्रीय रणनीतिक विकल्प बहुपक्षीय सगाई (Multilateral Engagement) है, जिसमें भारत BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation), IORA (Indian Ocean Rim Association), BRICS, ASEAN, और अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

BIMSTEC, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं, का लक्ष्य तकनीकी, आर्थिक और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देना है और यह भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के साथ भी संरेखित है।

IORA का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना है, जो समुद्री सुरक्षा, पोर्ट विकास और समुद्री संसाधन सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

इन बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से भारत ने न केवल क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है, बल्कि एक साझा सुरक्षा एवं विकास ढांचे की नींव भी रखी है।

आज के बहुध्रुवीय विश्व (Multipolar World) में, भारत की ये नीति विकल्प वैश्विक शक्ति संतुलन में उसकी भूमिका को सुदृढ़ करने में सहायक हैं। राजनयिक सगाई बिना हस्तक्षेप, सुरक्षा साझेदारी, आर्थिक कूटनीति, सीमा सुधार और बहुपक्षीय सगाई को संतुलित कर, भारत ने न केवल अपने हितों की रक्षा की है बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और साझा प्रगति को भी बढ़ावा दिया है। यह नीति नीतिगत दृढ़ता और सहयोग-आधारित दृष्टिकोण के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत को सक्षम बनाती है, जिससे एक अधिक समावेशी और स्थिर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में योगदान मिलता है।

आगे की राह: रणनीतिक अनुशंसाएँ (Way Forward: Strategic Recommendations):

दक्षिण एशिया की वर्तमान भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, विशेषकर बांग्लादेश में जारी राजनीतिक-सामाजिक उथल-पुथल के परिप्रेक्ष्य में, भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह तात्कालिक प्रतिक्रियाओं के स्थान पर दीर्घकालिक, सिद्धांत-आधारित और रणनीतिक रूप से संतुलित नीति अपनाए। भारत की "Neighbourhood First Policy" तथा "Act East Policy" की विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है।

सबसे पहली और केंद्रीय रणनीतिक अनुशंसा यह है कि भारत को "प्रो-स्टेबिलिटी, नॉट प्रो-रिजीम" (स्थिरता समर्थक, न कि किसी विशेष शासन समर्थक) दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अतीत में यह देखा गया है कि किसी एक राजनीतिक नेतृत्व या दल के साथ अत्यधिक निकटता, सत्ता परिवर्तन की स्थिति में भारत के हितों को कमजोर कर देती है। अतः भारत को बांग्लादेश की संस्थाओं—जैसे संसद, नौकरशाही, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक समाज—के साथ व्यापक और बहुस्तरीय संवाद बनाए रखना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित करेगा, बल्कि उसे "हस्तक्षेपकारी शक्ति" के आरोपों से भी बचाएगा।

दूसरी महत्वपूर्ण अनुशंसा भारत की विदेश नीति में मूल्यों और हितों के बीच संतुलन (Balance between Values and Interests) से संबंधित है। एक ओर भारत स्वयं को लोकतंत्र, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन का समर्थक मानता है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आर्थिक संपर्क जैसे ठोस राष्ट्रीय हित भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में भारत को सार्वजनिक मंचों पर नैतिक उपदेश देने के बजाय "शांत कूटनीति" (Quiet Diplomacy) को प्राथमिकता देनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों पर

संवाद द्विपक्षीय चैनलों, ट्रैक-1.5 और ट्रैक-2 डिप्लोमेसी के माध्यम से किया जाना अधिक प्रभावी और व्यावहारिक होगा।

तीसरी अनुशंसा के रूप में भारत को एक दीर्घकालिक पड़ोसी सुरक्षा सिद्धांत (Long-term Neighbourhood Security Doctrine) विकसित करने की आवश्यकता है। यह सिद्धांत केवल पारंपरिक सैन्य खतरों तक सीमित न होकर अवैध प्रवासन, कट्टरपंथ, संगठित अपराध, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को भी सम्मिलित करे। बांग्लादेश के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का सीधा प्रभाव भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ता है।

चौथी रणनीतिक दिशा क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने (Regional Security Architecture Strengthening) से जुड़ी है। भारत को BIMSTEC, IORA और BBIN जैसे मंचों को केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित न रखते हुए उन्हें क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद के प्रभावी मंचों के रूप में विकसित करना चाहिए। साझा समुद्री डोमेन जागरूकता, आतंकवाद-रोधी सहयोग, मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) तथा साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग बढ़ाना समय की मांग है। इससे बाहरी शक्तियों के रणनीतिक प्रभाव को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।

पाँचवीं अनुशंसा आर्थिक और विकासात्मक कूटनीति से संबंधित है। भारत को बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ समावेशी विकास साझेदारी (Inclusive Development Partnership) को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऊर्जा संपर्क, डिजिटल अवसंरचना, कौशल विकास और सीमा-पार व्यापार सुविधा जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत की “सॉफ्ट पावर” को मजबूती मिलेगी। यह दृष्टिकोण चीन की ऋण-आधारित परियोजनाओं के विकल्प के रूप में भारत को एक भरोसेमंद और उत्तरदायी भागीदार के रूप में स्थापित कर सकता है।

अंततः, भारत को अपनी रणनीति में रणनीतिक धैर्य (Strategic Patience) और संस्थागत निरंतरता को केंद्रीय स्थान देना होगा। दक्षिण एशिया की राजनीति स्वभावतः अस्थिर और जटिल रही है, जहाँ त्वरित

समाधान दुर्लभ हैं। ऐसे में भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अल्पकालिक राजनीतिक घटनाओं से विचलित हुए बिना, दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता, संप्रभुता के सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित नीति को निरंतर आगे बढ़ाता है।

समग्र रूप से, भारत के लिए आगे की राह एक संतुलित, बहुआयामी और दूरदर्शी रणनीति की मांग करती है—जहाँ स्थिरता को प्राथमिकता, मूल्यों और हितों का संतुलन, दीर्घकालिक पड़ोसी सुरक्षा दृष्टि और सुदृढ़ क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचा मिलकर भारत को न केवल एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित कर सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस अध्ययन का केंद्रीय तर्क स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि बांग्लादेश में उत्पन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता केवल एक आंतरिक संकट नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। बांग्लादेश और भारत के बीच ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा रणनीतिक अंतर्संबंध इतने गहरे हैं कि ढाका में होने वाला कोई भी बड़ा उथल-पुथल नई दिल्ली की सुरक्षा गणनाओं को सीधे प्रभावित करता है। अतः बांग्लादेश की अस्थिरता को भारत के लिए एक परिधीय समस्या मानना रणनीतिक भूल होगी; वस्तुतः यह भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा संरचना से जुड़ा एक केन्द्रीय सुरक्षा प्रश्न बन चुका है।

अध्ययन में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक क्षरण, आर्थिक दबाव, विदेशी ऋण निर्भरता, सामाजिक ध्रुवीकरण और उग्रवाद के पुनरुत्थान की प्रवृत्तियाँ भारत के लिए बहुआयामी जोखिम उत्पन्न करती हैं। अवैध प्रवासन, सीमा-पार अपराध, कट्टरपंथी नेटवर्क, नकली मुद्रा, हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कारक भारत की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत में। इसके साथ-साथ, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की बढ़ती उपस्थिति और रणनीतिक निवेश भारत के समुद्री हितों तथा Maritime Domain Awareness को भी चुनौती दे रहे हैं।

भविष्य के जोखिमों का आकलन यह संकेत देता है कि यदि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता और संस्थागत मजबूती सुनिश्चित नहीं की गई, तो यह संकट दीर्घकालिक रूप ले सकता है। कमजोर राज्य संस्थाएँ, युवाओं में बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और पहचान-आधारित राजनीति भविष्य में कट्टरपंथ और हिंसक अस्थिरता को और गहरा सकती है। ऐसी स्थिति में भारत को केवल प्रतिक्रियात्मक नीति तक सीमित रहना रणनीतिक रूप से अपर्याप्त होगा। इसके बजाय, एक दूरदर्शी, दीर्घकालिक और बहु-स्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो सुरक्षा, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता—सभी आयामों को एक साथ संबोधित करे।

रणनीतिक तात्कालिकता (Strategic Urgency) इस तथ्य से भी उत्पन्न होती है कि दक्षिण एशिया वर्तमान में तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन चुका है। यदि भारत समय रहते सक्रिय भूमिका नहीं निभाता, तो क्षेत्रीय शून्य को बाहरी शक्तियाँ भर सकती हैं, जिससे भारत का रणनीतिक प्रभाव क्षीण होने का जोखिम रहेगा। इसलिए, भारत के लिए यह अनिवार्य है कि वह pro-stability, not pro-regime दृष्टिकोण अपनाए—अर्थात किसी विशेष सरकार का समर्थन करने के बजाय बांग्लादेश की संस्थागत स्थिरता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामाजिक सामंजस्य को प्राथमिकता दे।

दक्षिण एशिया की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भारत की भूमिका केवल एक शक्तिशाली पड़ोसी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक Responsible Regional Stakeholder के रूप में उभरनी चाहिए। भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला (Regional Security Architecture) को मजबूत करने, आर्थिक अंतर्संबंध बढ़ाने, मानवीय और विकासात्मक सहयोग को संस्थागत रूप देने तथा बहुपक्षीय मंचों—जैसे BIMSTEC, IORA और संयुक्त राष्ट्र—के माध्यम से सामूहिक समाधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे न केवल बांग्लादेश जैसे देशों की स्थिरता को बल मिलेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में विश्वास-निर्माण और सहयोग की संस्कृति विकसित होगी।

अंततः, यह निष्कर्ष निकलता है कि बांग्लादेश की स्थिरता और भारत की सुरक्षा एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं। भारत के लिए यह समय निर्णायक है—या तो वह अल्पकालिक संकट प्रबंधन तक सीमित रहे, या फिर एक व्यापक क्षेत्रीय दृष्टि के साथ नेतृत्वकारी भूमिका निभाए। यदि भारत संतुलित कूटनीति,

समावेशी विकास सहयोग और सुदृढ़ सुरक्षा नीति को एकीकृत रूप में लागू करता है, तो न केवल बांग्लादेश संकट के नकारात्मक प्रभावों को सीमित किया जा सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया को स्थिरता, समृद्धि और सामूहिक सुरक्षा की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। यही इस अध्ययन का मूल संदेश और भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निष्कर्ष है।

संदर्भ सूची / References – Bibliography:

(क) पुस्तकें (Books):

बोस, सुगाता. A Hundred Horizons: The Indian Ocean in the Age of Global Empire. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006.

गांगुली, सुमित. India's Foreign Policy: Retrospect and Prospect. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2010.

मोहंती, बिस्वजीत. Bangladesh at Crossroads: Political Instability and Governance. सेज पब्लिकेशंस, 2018.

पंत, हर्ष वी. Indian Foreign Policy: An Overview. सेज पब्लिकेशंस, 2019.

रमेश, जयंत. Neighbourhood First: India's Regional Strategy. पेंगुइन इंडिया, 2021.

शाहिदुल्लाह, शाह एम. Bangladesh and Regional Security in South Asia. रूटलेज, 2017.

स्कॉट, डेविड. India's Role in the Indo-Pacific. पॉलिटी प्रेस, 2020.

(ख) शोध-पत्र एवं अकादमिक जर्नल (Journals):

अली, रशीद. "Political Instability in Bangladesh and Its Implications for South Asian Security." Journal of South Asian Studies, Vol. 42, No. 3, 2021.

भट्टाचार्य, देवप्रिया. "Democracy, Governance and External Influence in Bangladesh." Economic and Political Weekly, Vol. 56, No. 18, 2021.

दत्ता, प्रतिम. "India–Bangladesh Relations: Security and Strategic Dimensions." Strategic Analysis, IDSA, 2020.

हक, मोहम्मद नूरुल. "China's Strategic Footprint in Bangladesh." Asian Affairs, Vol. 51, No. 4, 2020.

पांडा, जगन्नाथ. "Bay of Bengal as a New Strategic Theatre." International Studies, Vol. 58, No. 2, 2021.

रॉय, अनुपम. "Migration, Border Management and India's Internal Security." Journal of Borderlands Studies, 2019.

(ग) थिंक टैंक रिपोर्ट्स (Think Tank & Policy Reports)

Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA). Bangladesh: Political Developments and Security Implications. नई दिल्ली, 2022.

United States Institute of Peace (USIP). Democracy and Stability in Bangladesh. वाशिंगटन डी.सी., 2021.

Observer Research Foundation (ORF). India's Neighbourhood Challenges. नई दिल्ली, 2023.

International Crisis Group. Bangladesh: Preventing Political Breakdown. ब्रुसेल्स, 2020.

Brookings Institution. China's Expanding Influence in South Asia. 2022.

(घ) समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ (Newspapers & Magazines)

The Hindu. "Political Crisis in Bangladesh and Regional Implications." विभिन्न अंक, 2020–2024.

Indian Express. "India's Security Concerns in Eastern Neighbourhood." विभिन्न अंक, 2021–2024.

Frontline. "Bangladesh in Turmoil: Democracy Under Stress." 2022.

The Daily Star (Bangladesh). "External Influence and Domestic Politics." विभिन्न अंक.

The Economist. "Bangladesh's Fragile Democratic Transition." 2023.

(ङ) सरकारी एवं आधिकारिक दस्तावेज़ (Official Documents)

भारत सरकार, विदेश मंत्रालय. India–Bangladesh Relations: Official Briefs. नई दिल्ली.

Ministry of Home Affairs, Government of India. Annual Report on Internal Security.

Bangladesh Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy and Regional Cooperation Reports.

BIMSTEC Secretariat. Regional Security and Cooperation Framework.

(च) वेबसाइट्स एवं डिजिटल स्रोत (Web Sources)

Institute for Defence Studies and Analyses (IDSA) – https://idsa.in

Observer Research Foundation (ORF) – https://orfonline.org

United Nations Development Programme (UNDP) – Bangladesh Reports

World Bank – Bangladesh Development Update

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) – South Asia Security Data

(छ) अन्य संदर्भ (Others)

Parliamentary Debates of India related to Neighbourhood Policy.

International Conference Papers on South Asian Security (2020–2024).

Interviews and expert commentaries published in strategic affairs magazines.